



राजस्थान के नेताओं में सचिन पायलट लगातार राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं और इस दौरान दोनों में लगातार चर्चा भी हो रही है। दूसरे दिन की यात्रा के दौरान राहुल गांधी सचिन पायलट के कंधे पर हाथ रखकर काफी देर तक चर्चा करते हुए नजर आए।

राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ने के लिये भुगतान मिला?

सिने स्टार स्वरा भास्कर ने कहा, "हाँ भुगतान मिला, जनता की शुभकामनाओं व पीठ ठोकने से, और भुगतान अभी भी मिल रहा है"

—सुजीत चक्रवर्ती—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर। सिने स्टार भास्कर ने जब यह कहा कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिये उन्हें कुछ मिला था तो भाजपा ईकोसिस्टम के टूर्नालिंग दिल एक क्षण के लिये बल्लियों उछल गया। लेकिन अगले ही क्षण उनका मन बैठ गया, जब स्वरा ने कहा कि "मुझे वहाँ अनेकानेक लोगों का असीम सम्मान, अपार प्यार एवं अपनापन मिला, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल थे, जो कांग्रेसी नहीं थे। भाजपा, जो इस बात से व्यकुल और हताश है कि अपने-अपने क्षेत्र के बहुत सारे सितारे राहुल गांधी की इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, ने दावा किया था कि उसने एक ऐसी टवीट खोजी है जो यह सिद्ध करती है कि राहुल गांधी की कांग्रेस इन लोगों को उनकी यात्रा में शामिल होने के लिये बड़ी मात्रा में पैसा दे रही है। भाजपा ने कहा, बल्कि अशिष्टता-पूर्ण संकेत दिया कि सिने स्टार तो अच्छी खासी धनराशि की खातिर 15 मिनट का कोई भी स्टांट देने के लिये तैयार हो जाते हैं। भाजपा के आई.टी. प्रकोष्ठ ने तो

- भाजपा के आई.टी. सैल की बड़ी अटपटी स्थिति हुई इस कथन से, क्योंकि वह बार-बार कह रहा था कि, फिल्मी हस्तियों को भारी राशि दी जा रही है, यात्रा से जुड़ने के लिये।
- आई.टी. सैल ने आत्म रक्षा में कहा, "सिने स्टार तो होते ही हैं सूटे।"

सत्तर वर्षीय कलामर्मज्ञ अमोल पालेकर को भी नहीं बख्शा, जिनका सारी दुनिया सम्मान करती है। वस्तुतः रिया सेन, पूजा भट्ट, रितेश देशमुख तथा अन्य ऐसी हस्तियों के "लाइव्स" तो राहुल गांधी को काफी पहले ही मिल गये थे लेकिन जब पालेकर यात्रा में शामिल हुये और राहुल की बाँह धामे हुये उनके साथ पैदल चले, तो भाजपा बुरी तरह हड़बड़ा गई। और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि भाजपा के सभी पूर्व युक्तियों और संकेतों की तरह, उसका प्रस्तावित शोर-शराबा, गौली फुलझड़ी की तरह, निरर्थक साबित हुआ। ऐसा तो होना ही था।

सही बात तो यह है कि बॉलीवुड की किसी भी हस्ती ने भाजपा के किसी भी निराधार आरोप का कोई जवाब नहीं दिया, उसे किसी प्रतिक्रिया लायक नहीं

समझा। और इस प्रकार की अगिन्परीक्षा में बॉलीवुड खरा उतरा। यह बात उस समय साफ हो गई, जब टाइम्स टी.वी. पर एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने स्वरा का इन्टरव्यू लिया। उन्होंने स्वरा से बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे वे भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुईं, उनके साथ पैदल चलते हुए उन्होंने क्या देखा, आदि-आदि। उनसे राहुल गांधी के बारे में भी प्रश्न किये गये। और अन्त में, उस प्रश्न की बारी आई, जो इन्टरव्यू का सबसे अहम प्रश्न था, बल्कि जिसके कारण इन्टरव्यू लिया गया था। उनसे पूछा गया: भाजपा ने कहा है कि यात्रा में शामिल होने के लिये, कई फिल्मी सितारों को कांग्रेस बड़ी धन राशि दे रही है।" स्वरा भास्कर, क्या आपको आपका भुगतान मिला गया?" स्वरा ने कहा, "हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों जिनमें ऐसे भी हैं, जो कांग्रेसी नहीं

हैं, का असीमित स्नेह, सम्मान एवं अपनत्व मिला।"

मेरे लिये यह एक पहेली है कि समाचार चैनल ने इन्टरव्यू के लिये स्वरा भास्कर को ही क्यों चुना। शायद इसलिये कि, इन तमाम सेलीब्रिटीज में, वे खुले एवं स्वतंत्र विचारों वाली कलाकार माने जाते हैं। वे सी.ए.ए. की विरोधी तथा मोदी की नीतियों के खिलाफ हैं। लेकिन सत्य सदैव ही कल्पना/कहानी की अपेक्षा अजनबी/अपरिचित हुआ करता है।

स्वरा ने कहा कि उन्हें पारिश्रमिक मिला, और हवाई अड्डों पर अपरिचित लोगों से अब भी मिल रहा है, जो उन्हें "स्वरा" बने रहने के लिये तथा उन बातों को कह देने के लिये धन्यवाद दे रहे होते हैं, जिन्हें कहने में लोग डरते हैं लेकिन जिन्हें कहा जाना बहुत जरूरी है। उन्हे "भुगतान मिला", उदाहरण के लिये, कॉफी शॉप पर काम करने वाले खालिद नाम के उस लड़के से, जिसने मुझे एक पत्र दिया और कहा: "आप नहीं जानती कि आप जैसे लोगों के कारण, हम भारत के मुसलमान स्वयं को कितना ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं।" बस, यही मेरा भुगतान है।" ये सेलिब्रिटीज राहुल के साथ क्यों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी 9 दिसम्बर को बच्चों के साथ जन्म दिन मनाने राजस्थान आ रही हैं

इसीलिए 9 दिसम्बर, भारत जोड़ो यात्रा के लिये अवकाश का दिन है

—रेणु मिश्र—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
झालावाड़ (राजस्थान), 6 दिसम्बर। सोनिया गांधी आगामी 9 दिसम्बर को अपना जन्मदिन अपने बच्चों के साथ मनाने के लिए पुत्री प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान आ रही हैं।

सूत्र बताते हैं कि गांधी परिवार द्वारा "मिशन राजस्थान" को फायनल टच दिए जाने की उम्मीद है, जो कांग्रेस नेतृत्व के लिए सिरदर्द बन चुका है। सूत्र कहते हैं कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए मूल रूपरेखा तय कर ली गई है और लम्बे समय से लम्बित

- गांधी परिवार, उस दिन रणथम्भौर जायेगा, साथ-साथ छुट्टी बिताते
- उसी दिन सोनिया गांधी, राहुल व प्रियंका, "मिशन राजस्थान" को "फाइनल टच" देंगे। यह माना जा रहा है कि, नेतृत्व परिवर्तन कार्यक्रम का मोटा-मोटी प्रोग्राम तो तय हो गया है और अब क्रियान्वयन कार्यक्रम की बारीकियां तय होंगी।
- जानकार सूत्रों का कहना है कि, राजस्थान के प्रभारी के पद पर रंधावा की पद नियुक्ति इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है। रंधावा "नो-नॉन्सेंस" नेता हैं पंजाब के, तथा अमरिन्दर सिंह को मु.मंत्री पद से हटाने में उनकी अहम भूमिका थी।
- गहलोत ने पूर्व प्रभारी अजय माकन को टारगेट बना लिया था, अतः संतुलन बनाए रखने की छवि को प्रदर्शित करते हुए रंधावा को नया प्रभारी बनाया गया है।
- रंधावा मंगलवार शाम को जयपुर पहुंच गये हैं, तथा कल से भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होंगे।

राहुल गांधी पहले से ही कोटा में हैं और उम्मीद है कि तीनों ही रणथम्भौर जाकर एक-दूसरे के साथ समय बिताएंगे। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिसम्बर का अवकाश घोषित किया गया है।

इस निर्णय पर अब अमल करने का समय है। सूत्र कहते हैं कि अजय माकन के स्थान पर रंधावा को ए.आई.सी.सी. महासचिव नियुक्त किया जाना इसी योजना का हिस्सा माना जा सकता है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉ. पूनिया का राहुल गांधी से दूसरा सवाल

नई दिल्ली/जयपुर 6 दिसम्बर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने भारत जोड़ो यात्रा पर आए राहुल गांधी से दूसरा सवाल किया, उनका पहला सवाल था किसानों की कर्जा माफी कब होगी जो उन्होंने 2018

- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान आए राहुल गांधी से दूसरा सवाल किया कि, राजस्थान की जनता को अपराधों से मुक्ति कब तक मिलेगी?

में वादा किया था। उन्होंने राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश है, लेकिन कांग्रेस सरकार के शासन में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद हिंसक हुआ

कर्नाटक के वासियों ने महाराष्ट्र से आ रही बसों को रोका, पत्थर बाजी की

—लक्ष्मण बैंकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर। भाजपा शासित दो राज्य-कर्नाटक एवं महाराष्ट्र एक बहुत छोटे से भूभाग, बेलागावी को लेकर आपस में लड़ रहे हैं तथा दोनों ही राज्य इस पर अपना दावा जता रहे हैं। मंगलवार को, सीमा के दोनों तरफ दोनों राज्य का झगड़ा जोर पकड़ गया तथा कन्नड़ प्रदर्शनकारियों ने उन बसों और ट्रकों पर पत्थर फेंके, जिनके रजिस्ट्रेशन नम्बर महाराष्ट्र के थे।

इससे पहले कि पुलिस इन कन्नड़ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेती, उन्होंने महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों को रोका, तथा उनमें से कुछ को क्षतिग्रस्त

- विवाद छोटे से क्षेत्र बेलागावी से संबंध रखता है। यह क्षेत्र 1960 के दशक में राज्यों की सीमाएं निर्धारित करते हुए, कर्नाटक को दे दिया गया था, हालांकि, इस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या मराठी है।
- शरद पवार ने धमकी दी कि, अगर महाराष्ट्र के वाहनों को हानि पहुंचाना जारी रहा तो, वो बेलागावी जाकर, आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।
- कर्नाटक व महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है।

भी कर दिया। लेकिन अब स्थिति नियन्त्रण में है, जबकि दोनों ही राज्यों के राजतना एक-दूसरे पर भारी बयानबाजी कर रहे हैं। तथा बेलागावी पर

अपने-अपने दावों को दोहरा रहे हैं। दरअसल, बेलागावी के अधिकांश लोग मराठी-भाषी हैं, लेकिन 1960 के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

16 दिसम्बर को होंगे हाई कोर्ट बार चुनाव

जयपुर, 6 दिसंबर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार के 16 दिसंबर को होने वाले चुनाव का रास्ता साफ कर दिया और इस मामले में चुनाव पर रोक लगाने की मांग करने वाली अपील को खारिज कर दिया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके के. भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश बीसीआई व अधिवक्ता सुमेर

- राजस्थान हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द करने की मांग करने वाली बी.सी.आई. की याचिका को खारिज कर दिया।

सिंह ओला की अपील को खारिज करते हुए दिए। अपील में एकलपीठ के गत 11 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसमें एकलपीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'तू डाल-डाल मैं पात-पात'

पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक दृष्टि से बांधने का प्रयास किया, रूसी ऑयल पर "प्राइस कैप" लगाकर, पर रूस ने ऑयल का उत्पादन घटाकर, विश्व की इकॉनमी को असंतुलित करने की धमकी दी

—अंजन राज—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर। तेल का वैश्विक बाजार एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है क्योंकि रूस के तेल की कीमत पर यूरोपीय यूनियन (ई.यू.) द्वारा तय की गई सीमा आज से लागू हो रही है। ई.यू. ने रूस के तेल के लिए 60 डॉलर प्रति बैरल की कीमत तय की गई है। तेल की कीमतें करीब 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं और ई.यू. द्वारा तय की गई कीमत वर्तमान कीमतों से अधिक कम नहीं है। वैश्विक मंदी और सभी देशों की आर्थिक वृद्धि दर से कमी की गंभीर चुनौती के बीच यह कदम विश्व की अव्यवस्था की संभावनाओं को और बिगाड़ सकता है। उभरती (अर्थ व्यवस्था और अन्य कमजोर देश और अधिक गंभीर अनिश्चितताओं का सामना कर सकते हैं।

- "प्राइस कैप" की बातचीत तो कई दिनों से चल रही थी, पर, इस बार सफल होती सी नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने धमकी दी है कि, अगर कोई देश रूस के प्राइस कैप प्रतिबंध को तोड़ कर ऊंचे दाम पर तेल खरीदेगा तो उसे, ऑयल के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक सुविधाएं, जैसे इंश्योरेंस, शिपिंग, ब्रोकरेज आदि, उपलब्ध नहीं कराई जायेंगी, जिन पर पश्चिमी देशों का स्वाभिमत्त्व है।
- पश्चिमी देशों को आशा है कि, इन सुविधाओं के उपलब्ध न होने के भय से, कोई भी देश ऊंचे दाम पर रूस का ऑयल नहीं खरीदेगा, और रूस की आमदनी कम हो जायेगी, तथा रूस के पास यूक्रेन युद्ध चलाने के लिये पैसा नहीं बचेगा।
- पर, यह भी सच है कि, अगर रूस ने अपनी ऑयल की सप्लाई बंद कर दी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तो, ऑयल उद्योग में भूचाल आ जायेगा, तथा ऑयल की कीमत आसमान छूने लगेगी।
- अगर अन्य ऑयल प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो यह भूचाल रोका जा सकता है। पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका के मित्र सऊदी अरब ने भी अमेरिका के दबाव के बावजूद ऑयल उत्पादन बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया है।

यूरोप के कीमत तय करने के परिणामस्वरूप अब कोई भी ई.यू. की तय कीमत से अधिक पर रूस से तेल खरीदेगा। उसे तेल इंश्योरेंस, शिपिंग और ब्रोकरेज जैसी सम्बद्ध सेवाएं और सुविधाएं नहीं नहीं मिल पाएंगी। जो कि

ऑयल की ग्लोबल डील का हिस्सा होती है। यदि रूस से तय कीमत से अधिक तेल खरीदा जाता है तो इससे रूस को अतिरिक्त आय का सौदा एक तरह से असंभव हो जाएगा। भारत ने घोषणा की है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए डिस्काउन्टेड पर रूस का तेल खरीदना जारी रखेगा। इसका मतलब होगा कि तेल की खरीद की तय कीमत से कम पर होगा, या भारत को शिपिंग, इंश्योरेंस व अन्य सुविधाएं अपने-आप जुटानी होंगी। ई.यू. और अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला था कि वह रूस से तेल की खरीद में कमी करे। युद्ध की समाप्ति के बाद वर्तमान साल में चीन और भारत रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदारों के रूप में उभरे हैं और उन्होंने अपने राजस्व को घाटे में जाने से बचाया है। यूक्रेन में युद्ध छेड़ने और वहां के

नागरिक टिकानों पर मिसाइल हमले जारी रखने के कारण ई.यू. ने रूस को दण्ड देने के लिए तेल की कीमत तय करने का फैसला किया है। पिछले कुछ समय से रूस के हमलों का केन्द्र बिन्दु यूक्रेन की इलैक्ट्रिसिटी और एनर्जी फैसिलिटीज रही हैं। इसका कारण यह है कि वह कड़क के की टण्ड के महीनों में यूक्रेन के नागरिकों को दण्डित करना चाहता है। कीमत नियन्त्रण तेल की बिक्री से प्राप्त होने वाली रूस की आय को सीमित कर देगा। रूस अपनी बजट जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय पर पूर्णतया निर्भर है। उसके तेल से प्राप्त राजस्व में भारी कमी होने से उम्मीद है कि इससे यूक्रेन में चल रहे सैन्य अभियान के लिए फंड जुटाने और युद्ध के खर्च वहन करने की रूस की क्षमता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय क्यों नहीं?

जयपुर, 6 दिसंबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 91 विधायकों को ओर से दिए इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने पर विधानसभा स्पीकर डॉ. सी.पी. जोशी और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वी.के. भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़

- राजस्थान हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर डॉ. सी.पी. जोशी और सचिव को नोटिस भेज कर जवाब मांगा।

की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे थे। इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)